

संख्या २२५०।। / XV-1 / २४ / ४७२७२

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,  
पशुपालन विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-१

देहरादून: दिनांक १४ जुलाई, 2024

**विषय:** नाबार्ड की आर०आई०डी०एफ०-xxix योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 949/नि०-५/एक(५९)/RIDF/2023-24 दिनांक 07.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधिक बजट प्रावधान ₹0 6100.00 लाख के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार अवशेष धनराशि ₹0 1498.75 लाख (₹0 1387.642 लाख नाबार्ड लोन व ₹0 111.08 लाख राज्यांश) अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है:-

(धनराशि लाख ₹० मे)

Name of the work	Total Cost	Eligible Cost	RIDF Loan	State Govt. Contribution	Previous Allotment	Current Requirement		
						NABARD Loan	State Share	Total
<b>1-Modernization, Automation &amp; Strengthening of Govt Sheep Breeding Farm</b>								
1.1-Sheep Farm Makku	496.19	489.86	465.36	24.50	139.608	162.876	15.925	178.801
1.2-Sheep Farm Pangu	499.31	492.94	468.29	24.65	140.487	163.902	16.022	179.924
1.3-Sheep Farm Samaliti	497.06	490.72	466.18	24.54	139.854	163.163	15.951	179.114
1.4-Sheep Farm Bangali	492.08	485.80	461.51	24.29	138.453	161.529	15.788	177.317
1.5-Goat & Rabbit sheep Farm Gwalandam	495.29	488.98	464.52	24.46	139.356	162.582	15.899	178.481
2- Construction of Govt. Veterinary Hospital at Waan	99.61	99.61	94.62	4.99	29.883	33.117	1.747	34.864
3- Construction of Pashu Chikitsalay Ramgarh	89.18	87.90	83.50	4.40	25.050	29.225	2.86	32.085
<b>4-Construction of Veterinary Hospital, Transit Hostel, Shades for Pack Animals with Basic Amenities at</b>								
4.1-Gaurikund	188.40	188.40	178.98	9.42	56.520	62.643	3.297	65.94
4.2-Rudrapoint, Kedarnath	464.96	464.96	441.71	23.25	139.488	154.598	8.138	162.736
4.3-Badi Linchauli	192.31	192.31	182.69	9.62	57.693	63.941	3.367	67.308
(5) Upgradation of Heifer rearing farm, Pashulok-Rishikesh	496.89	496.89	472.04	24.85	149.067	165.214	8.698	173.912
(6) Construction of Training Center at ULDB Rishikesh	195.05	195.05	185.29	9.76	58.515	64.852	3.416	68.268
<b>Total-</b>	<b>4206.33</b>	<b>4173.42</b>	<b>3964.69</b>	<b>208.73</b>	<b>1213.974</b>	<b>1387.642</b>	<b>111.108</b>	<b>1498.750</b>

2. नाबार्ड पोषित आर०आई०डी०एफ० फेज xxIx के अन्तर्गत उक्त 12 परियोजनाओं के सापेक्ष 30 प्रतिशत मोबलाईजेशन धनराशि रु० 1189.407 लाख तथा राज्यांश रु० 24.567 लाख सहित कुल रु० 1213.974 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या—170948, दिनांक 29.11.2023 तथा शासनादेश संख्या—175583, दिनांक 18.12.2023 द्वारा अवमुक्त की गयी है। अतः आपके पत्र दिनांक 07.06.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—201358 / 9(150)—2019 / XXVII(1) / 2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 के प्रस्तर—27 में दिये गये निर्देशों के अधीन पशुपालन विभाग के अन्तर्गत नाबार्ड पोषित आर०आई०डी०एफ० फेज XXIX के अन्तर्गत उक्त 12 परियोजनाओं हेतु अवशेष धनराशि रु० 1498.75 लाख (रु० 1387.642 लाख नाबार्ड लोन व रु० 111.08 लाख राज्यांश) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. प्रश्नगत परियोजना को इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की जा रही है कि परियोजना को उक्तानुसार स्वीकृत लागत में ही समयबद्धता एवं गुणवत्तापरक पूर्ण किया जायेगा एवं आंगणन का किसी भी दशा में पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।
2. नाबार्ड ऋण के रूप में अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित नाबार्ड से प्रतिपूर्ति दावा ससमय शासन तथा नाबार्ड को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। निदेशक पशुपालन, आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों का दायित्व होगा कि वे नाबार्ड से समन्वय स्थापित कर ऋण के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करेंगे, तथा कृत कार्यवाही से ससमय शासन को भी अवगत करायेंगे। इस सम्बन्ध में दिए गये निर्देशों का अनुपालन न किए जाने पर निदेशक पशुपालन/आहरण वितरण अधिकारी/संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
3. अवमुक्त/स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता / दुरुपयोग / दोहरीकरण (Doubling) निर्धारित मानकों के विपरीत निर्माण कार्य एवं न्यून गुणवत्ता पाये जाने पर निदेशक पशुपालन, आहरण वितरण अधिकारी, मुख्य अधिशासी अधिकारी य०एल०डी०बी०, संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी तथा कार्यदायी संस्था पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
4. निदेशक, पशुपालन / संबंधित अपर निदेशक, पशुपालन एवं संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा समय—समय पर किए जा रहे निर्माण कार्य, कार्य की गुणवत्ता एवं उपयुक्तता का निरीक्षण किया जायेगा तथा कार्य निर्धारित मानकों, डिजाईन एवं गुणवत्ता के विपरीत पाये जाने पर संबंधित कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा तत्संबंधी जाँच आख्या शासन को भी प्रेषित की जानी आवश्यक होगी।
5. उक्त धनराशि इस शर्त के साथ आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि कार्य योजना हेतु अनुबंधित कार्यदायी संस्थाओं को उनके साथ हुए अनुबन्ध/एम०ओ०य० हेतु भुगतान की निहित शर्तों के अनुसार कार्य की भौतिक प्रगति, उच्च गुणवत्ता एवं सन्तोषजनक कार्य की पुष्टि के पश्चात ही आवश्यकतानुसार भुगतान किया जायेगा।
6. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या—400 / xxvii(1) / 2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

7. स्वीकृत धनराशि के ब्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (यथा संशोधित नियमावली) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047 / XIV-219(2006) / दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में शासन की पूर्वानुमति के बिना अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
10. कार्य हेतु अनुमोदित आगंणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार दर से ली गयी हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
11. धनराशि का आहरण व व्यय तभी किया जायेगा, जब विभाग द्वारा नाबार्ड से योजनाओं को पूर्ण किये जाने की अवधि का विस्तार संबंधी स्वीकृति तथा प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करने के साथ नाबार्ड की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।
12. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत मदवार धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
13. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
14. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय तथा आगंणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु कार्यदायी संरक्षा के संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
15. कार्य की प्रगति निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश सं-०-४७५ / xxvii(7) / 2008 से दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संरक्षा से एम०ओ०य०० अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. स्वीकृत धनराशि का व्यय करने, कार्य पूर्ण होने पर भौतिक प्रगति, निर्माण कार्य एवं अधिप्राप्ति से सम्बन्धित सामग्री/उपकरणों के फोटो ग्राफ्स शासन को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक -4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-00-106-अन्य पशुधन विकास-98-नाबार्ड पोषित- 01-नाबार्ड पोषित योजनाएं के 53-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-201358 / 9(150)-2019 / XXVII(1) / 2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

**Signed by Rajendra Kumar  
Bhatt  
Date: 15/03/2024 04:40:03**  
संयुक्त सचिव

संख्या-२२५०१७ (1) / XV-1 / 24 / 47272 एवं तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर निदेशक पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमार्यू मण्डल, नैनीताल।
3. सहायक महाप्रबन्धक, नाबाड़, क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं०-४२, आई०टी० पार्क, सहस्राबद्धा रोड, देहरादून।
4. संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य अधिशासी अधिकारी, शीप बोर्ड, देहरादून।
6. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू०एल०डी०बी०, देहरादून।
7. मुख्य अधिशासी अधिकारी, हीफर रियरिंग फार्म, पशुलोक ऋषिकेश।
8. गार्ड फाइल।

( राजेन्द्र कुमार मट्ट )  
संयुक्त सचिव।